In May 1985, the State Government was informed that the deductions had been made by the FCI in accordance with the orders of the Government of India prevailing from time to time. In June, 1986, the State Government sought relaxation of the orders. The request is under consideraion.

बिहार में सिंचाई योजनाएं

3213. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार की बड़ी तथा मध्यम कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं और उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है। तथा ये कब से लम्बित पड़ी हैं और बिहार राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) डकरानाला परियोजना (मुंगेर) की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है तथा इससे खेतों को पानी मिलना कब से प्रारम्भ होगा ; और

(ग) डकरानाला परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस पर और कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1974 से 10 बृहद तथा 12 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनकी अनुमानित लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। बिहार में 17 बृहद, तथा 41 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं।

(ख) डकरानाला परियोजना लगभग आधी पूरी हो चुकी है तथा इसके चालू योजना में पूरी हो जाने की सम्भावना है। मार्च 1987 तक 2000 हेक्टेयर क्षमता का उपयोग किये जाने की आशा थी।

(ग) परियोजना की 41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में से मार्च, 1987 तक 22 करोड़ रुपए से व्यय की प्रत्याशा थी।

सूखा के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति

3214. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे की चपेट में आए राज्यों की संख्या कितनी है तथा ऐसे कितने स्थान हैं जहां गत वर्ष से लेकर चार वर्षों के दौरान लगातार सूखा पड़ रहा है और क्या सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावी प्रबन्ध किए हैं या कोई योजना बनाई है ; और

(ख) क्या सरकार सूखे का स्थायी हल निकालने के लिए सांसदों की एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति का गठन करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) वर्तमान मानसून अवधि के दौरान 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों ने सूखे की स्थिति की सूचना दी है। पिछले चार वर्षों से अर्थात् 1984–85 के बाद 6 राज्य अभाव की परिस्थितियों से ग्रस्त रहे है ?

भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशेष कदम उठाये हैं : (1) सूखा राहत कार्यों को करने के लिये राज्यों को मार्जिन धनराशि की सहायता देने के लिये प्रावधान किया गया है ;

(2) सूखे राहत कार्यों की देखभाल करने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। (3) राज्यों को आवश्यकतानुसार तदर्थ केन्द्रीय सहायता निमुक्त की जा रही है। (4) सूखा राहत उपायों के संबंध में भारत सरकार ने राज्य सरकारों

को विस्तृत अनुदेश जारी कर दिए हैं। (5) राज्यों को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में चारे और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विशेष और बहुत जरूरी उपायों को करने की सलाह दी गयी है। (6) किसानों को वैकल्पिक फसले बोने में जहां भी सम्भव हो समर्थ बनाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रबंध किये जायेंगे।

(ख) जी नहीं।

Foodgrain reserve under the south Asian security system

3215. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to Unstarred Question 2199 given in the Rajya Sabha on the 8th May, 1987 and state:

(a) whether a South Asian Food Security system is likely to be set up with a total reserve of 200,000 tonnes of foodgrains of which India is likely to contribute 150,000 tonnes;

(b) if so, the country where this reserve is likely to be kept; and

(c) the extent to which it is likely to be beneficial to India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Yes, Madam, there is a proposal to establish a SAARC Food Security Reserve of 200,000 tonnes of foodgrains, of which India's contribution is expected to be 153,200 tonnes.

(b) Under the proposed scheme, each member country will store its share of contribution to the Reserve within that counry.

(c) The Reserve would contribute to food security and collective self-reliance in the region.

Bee keepers in Punjab

3216. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Indian Express dated July 30, 1987 wherein it has been stated that Bee keepers of Punjab are in distress;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any steps are being contemplated by Government to help the Bee Keepers of Punjab.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CORPORATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Government is aware of the news item that appeared in the Indian Express dated July 30, 1987.

(b) and (c) Khadi and Village industry Commission is mainly concerned with Bee Keeping as one of the village industries included in its schedule. It is encouraging the promotion of Bee Keeping all over the country and also extends technical assistance including distribution of equipment as well as financial assistance for setting up of medium and semi-commercial apiaries and marketing facilities including working capital loan for purchase of honey from Bee Keepers for the development of Bee Keeping Industry to State Khadi and Village Industry. Boards, Registered Institutions and Bee Keepers Cooperatives. KVIC marketing assistance of honey is confined to the units assisted by it. There may be several other units/individuals outside the KVIC/State KVI Board's fold engaged in production and marketing of honey. The marketing problem has arisen obviously due to step up in production of honey refer exotic variety of imported bees by the Punjab Agricultural University.